**प्रेस विज्ञप्ति**

**अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कोविड-19 रोज़गार सर्वे**

मंगलवार, 12 मई, 2020

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोज़गार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भारत के 12 राज्यों में 4000 कर्मचारियों का विस्तृत फोन सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण में दस सिविल सोसाइटी संघठनों ने यूनिवर्सिटी का सहयोग किया है। इस सर्वे के शुरुआती परिणामों को हम मंगलवार, 12 मई को शाम 5 बजे, एक वेबिनार में प्रस्तुत करेंगे। आप से अनुरोध है की यूट्यूब लाइव पर हमसे जुड़ें। सर्वेक्षण से जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि आंकड़े एवं सहयोगी संगठनों का विवरण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जायेगी।

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए २४ मार्च से लगी तालाबंदी ने अर्थव्यवस्था पर और विशेष रूप से कमजोर, अनौपचारिक, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर गहरा वार किया है। इनका मुकाबला करने और अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करने के लिए हमे तत्कालीन उपायों के साथ साथ, मध्यम से लंबी अवधि के लिए, व्यापक नीतिगत कदमों की भी जरूरत पड़ेगी। हम आशा करते हैं कि इस सर्वेक्षण से निकले निष्कर्ष, नीतिगत हस्तक्षेपों को निर्धारित करने में मदद करेंगे।

यह सर्वे आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र (पुणे), ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में किया गया है। तालाबंदी लागू होने के बाद के रोज़गार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है। सर्वे में स्व-रोज़गार, दिहाड़ी मज़दूर और नियमित वेतन / वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। एक विस्तृत रिपोर्ट कुछ हफ्तों में जारी की जाएगी।

**सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष**

- दो तिहाई (67%) लोगों ने अपना रोजगार खोया है। शहरी क्षेत्र अधिक गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं । शहरी क्षेत्रों में 10 में से 8 (80%) और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 में से लगभग 6 लोगों (57%) ने अपना रोजगार खोया है।
- स्व-रोज़गार करने वाले (जिनके पास रोज़गार था) की औसतन साप्ताहिक आय रु 2240 से गिर के रु 218 हो चुकी है। (90% गिरावट)
- आकस्मिक (कैज़ुअल) श्रमिकों (जिनको रोज़गार मिला) की औसतन साप्ताहिक आय रु 940 से गिर के रु 495 हो चुकी है। (47% गिरावट)
- 51% वेतनभोगियों को या तो कम वेतन मिला है या कोई वेतन नहीं मिला है।
- लगभग आधे (49%) परिवारों ने बताया कि उनके पास एक सप्ताह के आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं है।

संक्षेप में, अर्थव्यवस्था और श्रम बाजार को भारी नुक्सान पहुंचा है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, आजीविका और रोज़गार अभूतपूर्व स्तर पर नष्ट हुए हैं। इस स्तिथि से निकलने का रास्ता धीमा और बहुत मुश्किल हो सकता है। तत्कालीन राहत योजनाएं गंभीर स्तिथि को देखते हुए अपर्याप्त हैं।
सर्वेक्षण के निष्कर्षों को देखते हुए, अध्ययन कर रही टीम ने निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है।इन प्रस्तावों का विवरण आने वाली रिपोर्ट में उपलब्ध होगा।

- पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए।
- दो महीने के लिए कम से कम रु 7000 प्रति माह का कॅश ट्रांसफर दिया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए भी इसकी आवश्यकता है।
- शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, नरेगा कार्यों के सतर्क उद्घाटन की तत्कालीन ज़रुरत है।
- मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं (यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज) में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की ज़रुरत है।